राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी के पुस्तक भण्डारों का मूल्य क्रमशः 18.60 लाख रु०, 53.00 लाख रुपये 25.00 लाख रुपये और 9.10 लाख रुपये हैं।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय अपने प्रकाशनों की बिक्री को आठ थोक विक्रेता एजेन्टों और 90 खुदरा एजेन्टों के जरिए तथा पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेकर प्रोत्साहित कर रहा है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने अपनी पुस्तकों की बिक्री और संवितरण के लिये एक मात्र संवितरकों को नियुक्त किया है, और इस प्रयोजन के लिए अब क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का भी प्रबन्ध कर रहा है।

साहित्य अकादमी ने नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित अपने कार्यालयों में बिक्री के प्रबन्ध किये हुए हैं और यह मुख्य एजेन्टों और पुस्तक विक्रेताओं की सेवाओं का उपयोग करती हैं, जिन्हें विशेष रियायतें दी जाती हैं। बिक्री को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से और अपने प्रकाशनों की विपणित करने के लिए अकादमी का पुस्तक प्रदर्शनियों आयोजित करने का प्रस्ताव हैं।

ललितकला अकादमी, पुस्तक विक्रेताओं की सेवाओं का उपयोग करने के अलावा पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों में भी भाग लेती हैं।

बीजों की सुधरी हुई किस्मों की सप्लाई के बारे में राष्ट्रीय बीज निगम की असफलता

3451. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :
श्री धनशाह प्रधान :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम कृषकों की मांग के अनुसार गेहूं, ज्वार तथा मक्का के बीजों की सुधरी हुई किस्मों को सप्लाई करने में असमर्थ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अब तक निगम द्वारा गेहूं, ज्वार, कपास तथा सब्जियां के बीजों की कितनी नवीनतम किस्में तैयार की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख). उन्नत बीजों के उत्पादन की व्यवस्था और किसानों में उनके वितरण के लिये मुख्य रूप से राज्य सरकारें उत्तरदायी होती हैं। राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम और तराई विकास निगम जैसे अखिल भारतीय बीज उत्पादक संगठन भी अखिल भारतीय महत्व की विभिन्न फसलों की संकर और अधिक उपज देने वाली किस्मों के उन्नत बीजों का उत्पादन करते हैं। सहकारी एजेंसियों और प्राईवेट बीज उत्पादक संगठन भी उन्नत बीजों का उत्पादन करते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम का बीज उत्पादन कार्यक्रम राज्य सरकारों से प्राप्त मांग-पत्रों और निगम द्वारा अपने विक्रेताओं के जरिए बीज की मांगों के लिये गये जायजों तथा सारे देश में बिक्री के साधनों पर निर्भर करता है। निगम द्वारा वितरित किये गए गेहूं, ज्वार और मक्का के बीजों की मात्रा में लगातार वृद्धि हुई है जो कि निम्न लिखित तालिका से स्पष्ट है :-

बीज का नाम	वर्ष	वितरित की गई मात्रा (क्विं में)
1	2	3
मक्का	1971–72	14476.39
	1972–73	24581.88
	1973–74 (दिसम्बर तक)	7459.27
ज्वार	1971–72	1462.27
	1972–73	6985.27
	1973–74 (दिसम्बर तक)	3632.49

1	2	3
गेहूं	1971–72	46885.95
	1972–73	62071.35
	1973–74 (दिसम्बर तक)	93684.57

(ग) यह निगम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य अनुसंधान संगठनों द्वारा विकसित की गई अखिल भारतीय महत्व की फसलों की किस्मों के बीजों के वर्धन की व्यवस्था करता है। इस समय यह निगम संकर मक्का, संकर चरी, संकर बाजरा, धान, गेहूं तिलहनों, सब्जियों, चारा आदि जैसी विभिन्न फसलों के बीजों की 200 किस्मों के बीजों की व्यवस्था करता है।

Functioning of Maulana Azad College of Technology, Bhopal

3452. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether there is any control of the Central Government over the functioning of Maulana Azad College of Technology, Bhopal when the Central Government are paying more than 75 per cent of their budget; and

(b) if not, reasons thereof?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN): (a) The Maulana Azad College of Technology, Bhopal, is administered by a Board of Governors consisting of 15 members which includes one representative of the Central Government and two representatives of the State Government as provided in the Memorandum of Association for the Maulana Aazad College of Technology Society. The Finance Committee scrtinizes the budget proposals of the College an dmakes its recommendations to the Board of Governors. On receipt of the Board's recommendation, the Central Government examines the proposals and makes the budget provision for the College. The Regional Officer of the Ministry is also a Member of the Finance Committee.

(b) The composition of the Society/Board of Governors is in accordance with the approved scheme for setting up of the Regional Engineering Colleges.

फालतू भूमि का वितरण

3453. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :

श्री जगन्नाथराव जोशी :

क्या कृषि मंत्री राज्यों में उपलब्ध फालतू भूमि के बारे में 25 फरवरी, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 657 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिकतम सीमा संबंधी नये कानूनों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप राज्यवार कितने परिवारों को फालतू भूमि उपलब्ध करके वितरित किये जाने की संभावना है और इसे कितनी अवधि में वितरित किये जाने का विचार है ; और

(ख) उनमें से कितने प्रतिशत हरिजन परिवार होंगे जिन्हें यह फालतू भूमि वितरित की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख). जोतों की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों के क्रियान्वयन के दौरान ही इस बात का ठीक-ठीक पता चल